

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(न.रा.रा.)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्त सिंह लिग्नी , आर०ए०एस०

अपील संख्या 17/2018

1- दीपसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति रावणा राजपूत , निवासी तंवरा , तहसील
लाडनू ,जिला नागौर, राजस्थान।

.....

बनाम

1- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडनू जिला नागौर राजस्थान।

.....

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री विकास ठोलिया, हाऊज अली एवं विद्वान कुडी, अधिवक्ता नगण , राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरुद्ध निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 15.03.2018

संख्या 94/2016 किस्म मुकदमा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 न्यायालय तहसीलदार लाडनू जिला नागौर राज० पीठासीन अधिकारी आदूराम मेघवाल आर.टी.एक्ट द्वारा राज्य बनाम दीपसिंह में पारित किया गया।

निर्णय

दिनांक- 23.03.2018

अपीलान्त की ओर से अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :-

1- यह है कि दिनांक 20.12.2016 को प्रत्यर्थागण संख्या 01 के रिपोर्ट अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम की धारा 91के तहत कार्यवाही करने बाबत प्रत्यर्था संख्या 01 के न्यायालय में पेश की जिस पर प्रत्यर्था संख्या 01 के न्यायालय में मुकदमा 94/16 अनुवान सरकार जारी पट्टा तंवरा बनाम बीरुराम किस्म मुकदमा धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 दिनांक 20.12.2016 को अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध

५

मुकदमा दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया
आगामी तारिख पेशी 11.01.2017 को फरमायी गई।

2- यह है कि दिनांक 11.01.2017 को अपीलार्थी को नोटिस जारी करने
की वजह से उपस्थित नहीं हो सका। दिनांक 30.01.2017 को अपीलार्थी
अधिवक्ता श्री छोगाराम बुरडक ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 06.02.
2017 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी का जवाब पेश किया। अप्रार्थी
अपने जवाब में जाहिर किया कि प्रार्थी आबादी क्षेत्र में मकानों बनाने का
कर निवास कर रहे हैं। इसलिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमी को
जाना न्यायोचित नहीं है। आपके द्वारा बताई गई मौजा तंवरा भी सरकारी
भूमि है। अप्रार्थी के जवाब के संदर्भ में पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख
निरीक्षक के बयान कलमबद्ध किये गये, जिसके अनुसार अप्रार्थी नम्बर
नम्बर 165 सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जो गैर मुमकिन
गौचर है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा पटवारी हल्का एवं भू
अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व बयानात का भलीभांति अवलोकन
किया गया। जिससे अप्रार्थी का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण
किया जाना देखूबी साबित होता है। मौजा तंवरा जागीर खसरा नम्बर रकबा
0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर पर मकान बनाकर राजकीय भूमि पर
अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राज0 भू अधिनियम
अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन है जो अतिक्रमण
की क्षेपी में आता है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर उक्त खसरा
नम्बर 165 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर से वेदना किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी पर वार्षिक लगान दर 0.50 से 60
गुणा से जुर्माना रूपये 14/- अक्षरे चौदह रूपये कायम किया जा रहा है।
अप्रार्थी से जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का, भौतिक रूप से बेधना हेतु
भू अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व कार्यालय
कार्यालय हाजा को तहरीर जारी हो।

3- यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.
2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील निम्न आदेशों पर
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

-: अपील के आधार :-

(1) यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश एवं दण्डादेश
दिनांक 15.03.2017 को पारित करने में प्राकृतिक न्याय से सिद्धांतों को
अवहेलना की है। अपीलार्थी को गवाह पेश करने व मौखिक रूप से जवाब
का कोई अवसर नहीं दिया गया इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा पारित आलौच्य आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को
अपील अपारस्त किये जाने योग्य है।

31

- 2- यह है कि अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील को कन्टेस्ट करने हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति भी की गयी थी एवम अपीलार्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया गया था उसके बावजूद दिनांक 08.03.2017 को व निर्णय के दिन दिनांक 15-03-2017 को अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति की गई जिससे स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। आदेशिक दिनांक 15.03.2017 से भी प्रमाणित है। उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है जो अधीन अपास्त किये जाने योग्य है।
- 3- यह है कि पटवार हल्का द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच के दबाव में उक्त कार्यवाही पेश की जबकि उक्त तीनों खसरान् में करीब 150 परिवार अपने-अपने मकान बनाकर निवास करते आ रहे हैं। इस कारण 166 परिवारों के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखल करने का प्रयास पूर्ण कार्यवाही की है तथा शिकायत कर्ता राजनितिक प्रतिस्पर्दा को उक्त कार्यवाही कर अपनी राजनितिक रंजिश निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस कारण 166 परिवारों में से मात्र 35 परिवारों के विरुद्ध झुठी कार्यवाही कर कार्यवाही की है जो अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
- 4- यह है कि अपीलार्थी का मकान आबादी भूमि ग्राम तंवरा में बनाया गया है जिसमें अपीलार्थी के द्वारा घरेलू लाईट व पानी कनेक्शन ले रखा गया तथा सदीन काल से मकान बने हुये हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी आबादी क्षेत्र तंवरा में मकान कर निर्माण कर निवास कर रहे हैं। जो अपीलार्थी अतिक्रमी नहीं है। उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है जो अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
- 5- यह है कि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थागण संख्या 02 की केवल मात्र दिनांक 15.03.2017 के बयान के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित कर दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को पारित फरमाया। इसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य का सर्वेक्षण नहीं किया है इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

21

- 6- यह है कि अपीलार्थी के विरुद्ध खसरा नम्बर 165 रकबा 0.10 बीघा के स्थान गैर मुमकिन गौचर पर अतिक्रमी मानकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील अपास्त किये जायें जायें है।
- 7- यह है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया आदेश नहीं है। इस कारण विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को अपास्त फरमाया जावे।
- 8- यह है कि अपीलार्थी की अपील विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनू जिला नागौर के विरुद्ध है। इस कारण उक्त अपील को माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।
- 9- यह है कि अपीलार्थी को नोटिस मिला तथा अपीलार्थी ने उक्त नोटिस का जवाब अपने अधिवक्ता के माफत दिया गया था फिर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थित रहने के कारण उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। उक्त आलौच्य आदेश को अपील अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2018 को प्राप्त की इसलिए अपील अपास्त फरमाया है।
- 10- यह है कि अन्य उजरात बर उक्त अर्ज किये जायेगे।

अतः अपीलार्थी की अपील पेश कर माननीय न्यायालय से विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अन्वयित करने की प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को अपास्त फरमाया जावे एवं विकल्प में अपीलार्थी को उक्त आदेश को अन्वयित करने की प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को अपास्त फरमाया जाकर इस निर्देश के साथ पत्रावली को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में सुनवाई का, उक्त आदेश व साक्ष्य, दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर देकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

यह अपील अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास शर्मा द्वारा पेश की गयी। जो दिनांक 07.3.2018 को दर्ज रजिस्टर में दर्ज कर रैस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा अधिनस्थ न्यायालय को रिकॉर्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश व नोटिस तामिल होकर दिनांक 19.4.2018 को प्राप्त हुवे जो शाम 5 बजे तक

21

किये गये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड दिनांक 11.5.18 को प्रस्तुत हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पटवारी पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन व मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्त अप्रार्थी द्वारा ग्राम मौजा तंवरा जागीर के ख0नं0 165 ख0नं0 0.10 बीघा गैर मु0 गोचर पर मकान बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत 14/- रूपये का दण्ड आरोपीत किया गया।

गौचर की जमीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है जिसमें धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत उक्त पर किसी प्रकार के खातेदारी अधीन प्राप्त नहीं होते हैं। न ही गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पट्टा जारी किया जा सकता है। अप्रार्थी ने स्वयं अपने लिखित जवाब में बताया है कि वह आबादी क्षेत्र में राजकीय भूमि पर मकान का निर्माण कर रहा कर रहा है। पटवारी हल्का तंवरा व भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में भी अप्रार्थी को गै0मु0गोचर भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया है। पट्टे बिना नियमन के गौचर भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तथा यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अप्रार्थी को सुना नहीं गया है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय की अधिका दिनांक 22.2.17 में अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.3.17 को किया गया निर्णय विधी सम्मत है।

21

∴ आदेश ∴

अतः अपीलान्त की अपील खारिज की जाकर
अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.03.2017 बहाल रखा
जाता है।



(बलवन्त सिंह सिंघाणी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना जिला नौदर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बलवन्त सिंह सिंघाणी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नौदर)